

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46]

नई दिल्ली, शनिवार, भवम्बर 15, 1969 (कार्तिक 24, 1891) 🚟 🗟

No. 461

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1969 (KARTIKA 24, 1891)

इस जान में जिल्ला बुट संख्या की जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के क्य में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

मोटिस

(NOTICE)

नीचे किस्से भारत के असाधारण राजपन 13 अक्तूबर 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं:

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 13th October 1969;

अं क	संख्या और तिथि	द्वारा जारी किया गया	विषय
(Issue No.)	(No. and Date)	(Issued by)	(Subject)

171 No. 168-ITC (PN)/69, dt. 13th Oct. 69. Ministry of Foreign Trade & Supply.

Import of fruits, dried, salted or preserved all sorts, N.O.S. excluding Dates(i) [S.No. 21(a)(ii)(IV)], (ii) Dates [S.No. 21(b) IV], (ii), (iii) Medical Herbs (Crude Drugs) (S.No. 87—109-IV), (iv) Asafoetide [S.No. 31(b)/IV and other Misc. items from IRAN during Oct. 1969—March 1970.

कपर लिखे असाधारण राजपत्नों की प्रतियां प्रकाशन प्रवन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र मेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रवन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होन की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

	वषय-सूची	(CONTENTS)	
माग ।खंब ।(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर)	पृष्ठ	भाग IIखंड 3उप-खंड (2)(रक्ता मंत्रात्रय	पृष्ठ
भारत सरकार के मंत्रालयों औ र उच्च तम		को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों	
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर		औ र (संच-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को	
नियमों, विनियमों सथा आदेशों और		छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के	
संकल्पों ने सम्बन्धित अधिसुचनाएं 🔒 🧓	795	अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश	
भाग 1		और अधिसूचनाएं	4757
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम		भाग II— खांड 4— रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित	
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी		विधिक नियम और आदेश	5 59
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों		भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा	•
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 📌		आयोग, रेल प्रशासन, उच्च स्पायालयों	
भाग Iखंड 3रक्षा मंद्यालय द्वारा जारी की गई		और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन	
विधितर नियमों, वि निय मों, आदेशों भौर		कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1143
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	83	भाग III — खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा	
भाग ।खंड 4रक्षा मंत्रालय दारा जारी की गई	•	जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	409
अफसरों की नियुक्तियों. पदौ <mark>न्नतियों, छुट्टियो</mark> ं		भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके	110
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1105	प्राधिकार से जारी की गई। अधिसूचनाएं . भाग III—-खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की	113
भाग ॥खंड 1अधिनियम, अध्यादेण और विनियम		गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं,	
भाग 🏻 - ग्यंड 2 विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी		गर्व । यायक्ष वावसूचनाए । जनम आवसूचनाए, आवेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	0 0 0
श्रवर समितियों की रिपोर्ट		आवस, विज्ञापन आर नाटस शानल ह . भाग IVनैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी	6 9 7
		भाग 1४गर-सरकारा व्यान्तया बार गर-सरकारा संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	221
भाग 11 खंड 3 उप-खंड (1) (रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों		सस्याजा का पशायन तथा नात्वतः पूरक संख्या 46	221
का छाड़कर) भारत सरकार के मन्नालया और (संघ-राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को		रूपा पर्वा के0—— 8 नवम्बर 1969 को समाप्त होने बाले	
लार (सव-राज्य क्रेन्न के प्रशासना का छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी		सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1945
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और		18 अक्तूबर 1969 को समाप्त होने बाले सप्ताह	1040
आरी किए गए साधारण नियम (जिनमें		के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे	
साक्षारम ध्रकार के आदेश, उप-नियम		अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी	
त्राधि सम्मिलित हैं)	3 5 03	बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकर्डे.	1959
**	0000		
PART 1Section 1—Notifications relating to Non- Simutory Rules, Regulations, Orders	Page	PART II—SECTION 3.—Sus-Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the	Pago
and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than		Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	
the Ministry of Defence) and by the	40 *	by the Central Authorities (other than the	4757
Supreme Court	795	Administrations of Union Territories) PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders	4757
pointments, Promotions, Leave etc. of		notified by the Ministry of Defence	559
Government Officers issued by the Minis- tries of the Government of India (other		PART III—SECTION 1.—Notifications Issued by the Auditor General, Union Public Service	
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1287	Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Sub-	
PART I Section 3 Notifications relating to Non-		ordinate Offices of the Government of India	1143
Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of	0.0	PART III—Section 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta.	409
Defence PART I Section 4.— Notifications regarding	83	PART III—Section 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commis-	
Appointments, Promotions, Leave etc. of	110#	sioners	113
Officers issued by the Ministry of Defence PART II—Section 1.—Acts, Ordinances and Regu-	1105	including Notifications, Orders, Adver-	
lations		tisements and Notices issued by Statutory Bodies	697
PART II - Section 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills		PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	221
PART II—SECTION 3. —SUB-SEC. (i)—General		SUPPLEMENT No. 46—	221
Statutory Rules (including orders, byc- laws, etc., of general character) issued by		Weekly Epidemiological Reports for week- ending 8th November 1969	1945
the Ministries of the Government of ladia (other than the Ministry of		Births and Deaths from Principal diseases	1773
Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union		In towns with a population of 30,000 and over in India Juring week-ending 18th	
Terruories)	3503	October 1969	1959

भाग I—खण्ड । (PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जाशी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

पैद्रोलियम तथा रसायन और जान सथा भातु मंत्रालय (रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1969

सं० 4(40) / 67-केमी-1-केन्द्रीय सीरा बोर्ड की स्थापना के बारे में 19 मई, 1969 को नई दिल्लो में उत्पादन णुल्क राज्य-मिन्त्रयों के सम्मेलन (एक्साईज स्टेट मिनस्ट्रज कान्फ्रेंस) में लिए गए निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतत्-द्वारा केन्द्रीय सीरा बोर्ड की नियुक्ति करती है। बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा:-

- (1) पैट्रोलियम तथा २स यन और खान चैयरमैन तथा धातु मंत्री
- (2) पैट्रोलियम तथा रसायन के राज्य मंत्री सदस्य
- (3) समस्त राज्यों के उत्पादन-शुल्क मंत्री सदस्य
- (4) सचिव, पैट्रोलियम और रसाया विभाग स**दस्**य
- (5) सचिव, खाद्य विभाग सदस्य
- (6) संपुक्त सचिव (रसायन) पैट्रोलियम सचिव सथा सायन और खान तथा धातु भंजालय
- (7) विकास अधिकारो (अन्कोहन) तक- उप-सचिव नीको विकास का महा-निदेशालय

बोर्ड को खाण्ड-मौसम के बौरान दो बार बैठकें होंगी अर्थात, एक बार खाण्ड-वर्ष (सूगर यीअर) के आरम्भ में तथा दूसरी पेरना-मौसम (क्रिशिंग सोजन) के अन्त में । बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्न प्रवार होंगे :-

- (1) सम्बद्ध राज्य सरकारों और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सीरा/अल्कोहल/शर्करा के उत्पादन के बारे में आवश्यक दिता इकट्ठा करना।
- (2) सीरा के राज्य नियंत्रकों/उत्पादन शुल्क आयुक्तों की सूचना के लिये सीरा/अल्कोहल के अन्तराज्य आर्बेटन को तैयार करने के बारे में खाण्ड-मोसम के शुरु में. तरजोहन नवम्बर के मध्य में तथा पेरना मौसम के अन्त में अर्थात अप्रैल के अन्त में बैठक बुलाना ।
- (3) उचित दित्ता के एकत्रण द्वारा विभिन्न राज्यों में सीरे के मूल्य पर निगहरानी रखना और जिन राज्यों में अल्कोहल तथा सीरा फ:कार् है और जो अन्य राज्यों को फालतू अल्कोहल तथा सीरा देते हैं इन पाज्यों में इन

मदों पर लगाये जाने वाले विभिन्न करों को दरों में एकरूपता लाने का यस्त करना।

- 2. केन्द्रीय सीरा बोर्ड से अतिरिक्त, एक कार्यकारणी समिति होगी जिसका गठन निम्न प्रकार होगा:---
 - (1) संयुक्त सचिव (रसायन) पैट्रोलियम चैयरमैन तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय
 - (2) राज्यों के उत्पादन गुल्क विभाग में स**द**स्य संचिवतथा राज्य उत्पादन-शुल्क आयुक्त
 - (3) विकास अधिकारौ (अरूकोहल). तकनोको सचिव विकास का महानिदेशालय
- कार्यकारणो समिति के विचारार्थ विषय निम्न होंगे:---
 - (1) औवटनों के अनुसार प्रेषणों को प्रगति के मूल्यांकन के लिये विभिन्न राज्यों में समय-समय पर बैठकें बुलाने हेतु, प्रादेशिक समितियों का स्थानना करना तथा सम्बद्ध रेल्वेज के परामर्ग से माल उठवान (off take) पर निगहरानो रखना।
 - (2) प्रभावकारी कार्यन्यन हे जिले कहेकिन समितियों को सिफारियों के अनुसार तथा बोर्ड के चैथारीन को स्वाकृति से अन्तिराज्य बोजटनों की, जहां कहीं जायण्यक हो, उचित तराके से पुनराक्षाय करना आह इस बार में बोर्ड के सदायों को सूचित रखना।
 - (3) इस सम्बन्ध में उत्पन्न हुई समस्याओं के पिटान हे लिए समय-समय पर बैठक बुजाना ।

आर॰एस॰ गोपालन, अवर सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्लो, दिनांक 27 अक्तूबर 1969

सं०एफ० 22/1/69 सें०ए० I(2) — इस मंबालय े दिनांक 23 अप्रेल, 1966 को अधिमूचना सं० 14/3/65-चो०5 में अधिक संगोधन करते हुए डा०बो०सो० चकार्यी इतिहास अनुभाग रक्षा मंबालय को डा० एस० एन० प्रसाद के स्थान पर भारतीय इतिहास अभिलेख आयोग का साधारण सदस्य नियुक्त किया जाता है। फितहाल उनको नियुक्ति को अवधि 3 अप्रेल, 1971 तक होगो।

ए० एस० तलवार, अवर सचिब

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1969

विषय--विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक सेत्र के उपकर्मों की राष्ट्रीय एकता समितियों को समस्वय समिति की स्थापना

सं० एक० 5-1/69-एन०आई०सी०—देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों में पारस्परिक सद्भावना तथा सदाशयता को बढ़ावा देने के लिये गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर विभिन्न विश्व-विद्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में, राष्ट्रीय एकता समितियां स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति की राष्ट्रीय एकता उप-समिति ने एक परियोजना चाल की थी।

क्योंकि राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति की राष्ट्रीय एकता उप-समिति को समाप्त किया जाने वाला है, इसलिये भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता समितियों के लिये एक समन्वय समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि राष्ट्रीय एकता समितियों का कार्य हाथ में लिया जा सके और राष्ट्रीय एकता परिषद् के तत्वाधान में इन समितियों के कार्य को नियमित उनका मार्गदर्शन तथा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सके।

संरचना

समन्वय समिति का गठनं इस प्रकार होगा:--

- 1. श्रष्यक--शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री---पदेन
- सदस्य—राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति की राष्ट्रीय एकता उप-समिति तथा राष्ट्रीय एकता परिषद् के 6 सदस्य ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय इस समिति की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा तथा आवश्यक सचिवालयीय सुविधा प्रदान करेगा। कार्यविधि

समिति के सदस्यों की कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगी, बगर्ते कि,

- (i) सिमिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य के रूप में बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर हैं, जिसके आधार पर वे सिमिति के सदस्य हैं।
- (ii) नामजद सदस्य, नामजद करने वाले प्राधिकारी की इच्छा पर्यन्त पदधारी रहेंगे ।
- (iii) किसी सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण गदि समिति में कोई स्थान रिक्त होगा, तो उक्त रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष की बकागा अविधि तक ही पदधारी रहेगा।

बैठको

राष्ट्रीय एकता समितियों की समन्वय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी । किन्तु, अध्यक्ष आवश्यकता-नुसार किसी भी समय बैठक बुला सकता है।

कार्य

समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:--

- (1) राष्ट्रोय एकता परिषद् के तत्वावधान में राष्ट्रीयएकता समितियों को नियमित करना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उनको वित्तीय सहायता देना ।
- (2) ऐसे सभी विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में एसी समितियां स्थापित करना, जहां वे विद्यमान न हों।

- (3) इन समितियों के कार्य को व्यापक तथा विस्तृत करने के लिये, निम्नलिखित कार्यों को प्रोत्साहन करना:—
- (i) छात्रों के दलों को एक अथवा दो प्रोफेसरों अथवा प्राध्यापकों के साथ अन्य भाषाई तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में भेजना ताकि उन्हें उक्त विश्वविद्यालय और उसके आसपास की जनता से सीधा परिचय मिल सके।
- (ii) राज्य/क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय आधार पर सेमिनार आयोजित करने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना सया उनकी सहायता करना।
- (iii) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने तथा साम्प्रदायिकता, भाषाई तथा अन्य कटुताओं को दूर करने के लिये अभिभाषणों, वाद-विवादों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (iv) ऐसी अन्य योजनाएं तैयार करना जो विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करें।

मावेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संबीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आयोजना आयोग, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सर्वेसाधारण की सूचनार्ष भारत के राजपत्न में प्रकाशित कर दिया जाये।

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव

धन, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) संकल्प

नई दिल्लो-11, विनांक 23 अक्तूबर 1969

विषय : पुनर्वास बोर्ड का गठन

सं० 4(8)/69-बी०ओ०आर०→भारत सरकार ने पुनर्यास बोर्ड की सदस्यता से इंडिया आक्सीजन लिमिटेड के प्रबन्ध निर्देशक श्री ए०के० सेन का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। इन की नियुक्ति भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) के संकल्प संख्या 3(5)/67-आर०एच० बी० दिनांक 30 जनवरी, 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

भावेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्न-लिखित को भेजी जाए :--

- 1. बोर्ड के सभी सदस्य ।
- 2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- योजना आयोग, प्रधान मंत्री का सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय और राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैनिक सचिव।
- 4. राज्य सरकारों तथा संध शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाणित को जाए।

बी० नंजप्पा, सचिव

MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue and Insurance

NOTICE

New Delhi, the 27th October 1969

Appointment of Valuers under Section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953.

No. 5/77/68-E.D.—The following additions to this Ministry's notice of even number dated the 6th July, 1968 are hereby notified for general information:—

The Central Government propose to appoint qualified persons as Valuers for caradamom estates. The persons so appointed will be categorised as "Specialist in Cardamom Plantation". Accordingly, in para 2 of the said notice after S. No. 11, the following shall be added—

12. "Cardamom Plantation".

In order that a person may be eligible for appointment as a valuer in this category he must satisfy the qualifications mentioned below:—

(1) The valuer must be the owner or manager of Cardamom Plantation of the size of 100 acres;

and

(2) he must have at least seven years' experience in the plantation line.

This will appear as item (X) of para 3.

2. The other conditions mentioned in the earlier notice including the scale of charges fixed for remuneration of valuers remain unchanged.

BALBIR SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES AND METALS

Department of Chemicals

New Delhi, the 27th October 1969

No. 4/40/67/Ch.I.—1. In pursuance of the decision taken at the State Excise Ministers' Conference held in New Delhi on the 19th May, 1969, for the constitution of Central Molasses Board, the Central Government hereby constitute the Central Molasses Board. The composition of the Board will be as follows:

Chairman

 Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.

Members

- (2) Minister of State for Petroleum and Chemicals.
- (3) Excise Ministers of all States.
- (4) Secretary, Departments of Petroleum and Chemicals.
- (5) Secretary, Department of Food.

Member-Secretary

(6) Joint Secretary (Chemicals). Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines and Metals.

Deputy Secretary

(7) Development Officer (Alcohol), Directorate General of Technical Development.

The Board will meet twice during the sugar season once at the beginning of the sugar year and again at the end of the crushing season. The functions of the Board will be as under:

- (1) To collect necessary data in respect of production of molasses/alcohol/sugar from the respective State Governments and the Ministry of Food and Agriculture,
- (2) To hold a meeting at the beginning of the sugar year, preferably in the middle of November and at the end of the crushing season, i.e. at the end of April, to formulate the inter-State allocation of molasses/alcohol for communication to the State Controllers of Molasses/Excise Commissioners.

- (3) To keep a watch over the price of molasses in the various States by collection of suitable data and to attempt a uniformity in the rates of various levies made by surplus States on alcohol and molasses released to other States.
- 2. Apart from the Central Molasses Board, there will be a Working Committee of the following composition:

Chairman

 Joint Secretary (Chemicals) Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines & Metals.

Members

(ii) Secretaries to Government in the Excise Department of the States and State Excise Commissioners.

Secretary

- (iii) Development Officer (Alcohol) Directorate General of Technical Development.
- 3. The functions of the Working Committee will be as follows:
 - To constitute regional committees to hold meetings from time to time in different States for the purpose of assessing the progress of releases in accordance with the allocations and watching the offtake in consultation with the concerned Railways.
 - (2) To revise the inter-State allocations wherever necessary suitably for effective implementation in accordance with the recommendations of the regional committees with the approval of the Chairman of the Board and keep the members of the Board informed.
 - (3) To meet from time to time to deal with the connected problems that may arise.

R. S. GOPALAN, Under Secy.

Department of Petroleum and Chemicals

New Delhi, the 29th October 1969 RESOLUTION

No. 55(17)/69-Ferts.II.—In modification of the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Chemicals) Resolution No. Ferts. 11/55/17/69, dated 5th August, 1969, after paragraph 4, the following paragraph shall be added, namely:—

"4-A. The provisions of sub-section (2), Sub-section (4) and Sub-section (5) of Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 shall apply to the Commission".

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

Ordered further that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India

M. RAMAKRISHNAYYA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

Department of Family Planning

New Delhi, the 1st November 1969

RESOLUTION

No. 12-21/68-FP(Grants).—In supersession of the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Department of Family Planning Resolution No. 14-1/67-C&C(FP), dated the 30th December, 1967 the Government of India is pleased to reconstitute the Demographic and Communication Action Research Committee to consist of the following persons:—

Chairman

1. Dr. B. N. Ganguli

Members

2. Dr. C. N. Vakil.

- 3. Dr. P. S. Lokanathan.
- 4. Dr. S. Bhagavantham,
- 5. Prof. P. N. Dhar.
- 6. Dr. Andre Beteille.
 - 7. Dr. Pramod Vyas.
- Commissioner (MP & MCH), Depttt. oof Family Planning, New Delhi.
- Director, Central Statistical Organisation, Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 10. Registrar General of India.
- Director, Demographic Training and Research Centre, Bombay.
- 12. Officer on Special Duty (Evaluation). Department of Family Planning, New Delhi.

Member-Secretary

- 13. Director, Central Family Planning Institute, New Delhi.
- 2. The Committee may co-opt additional Members for ad-hoc purpose.
 - 3. The functions of the Committee will be:-

(A) Concerning Demography.

- To advise on research and studies on inter-relationship between economic, social and population changes on the reproductive pattern, attitudes and motivation affecting the size of the family;
- (ii) to advise on the programme of training and research keeping in view that such training and research will assist the Government to take action in the economic and social fields and thereby facilitate a sound national programme of re-construction;
- (iii) to co-ordinate demographic research schemes receiving financial assistance from the Government of India:
- (iv) to review progress made in the centres receiving financial assistance from the Ministry of Health, Family Planning & Works, Housing & Urban Development; and
- (v) to examine and make recommendations on proposals which may be received by the Ministry of Health, Family Planning, Works Housing and Urban Development for financial assitance for conducting demographic research.

(B) Concerning Communication Action Programme.

- to advise on and co-ordinate Family Planning Communication Research Programme;
- (ii) to review the progress of Family Planning Communication Research;
- (iii) to examine and make recommendations on the proposals for Family Planning Communication Research referred to it;
- (iv) to suggest other measures in furtherance of the objectives of the scheme; and
- (v) to recommend applicants for grant of fellowships for Family Planning Communication Research.
- 4. The life of the Committee will be two years from the date of this notification.
- 5. Non-Official members of the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowance for attending the meetings of the Committee, as admissible to an Officer of the highest grade in Class I of the Central Services. Prior approval of the Government shall be taken before any non-official member is authorised to travel by air or Airconditioned Coach. Members of the Committee who are Government Servants will draw travelling and daily allowance as admissible to them from the same source from which their salary is drawn.
- 6. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Major Head 30-B Public Health B.2 Grants for Public Health Purposes B.2(4)—Family Plan-

ning (Plan) B.2(4)(3) Research—(a) Central Family Planning Institute, New Delhi under Demand No. 39-Medical and Public Health for the year 1969-70. The expenditure during the subsequent years may be met from the funds, as may be voted by the Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations.

Ordered further that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

D. N. CHAUDHRI, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

Department of Agriculture

New Delhi, the 28th October 1969

RESOLUTION

No. 19-134/67-DD/LDI.—Shri V. T. Nagpure, Member Rajya Sabha and Maullana Ishaq Sambhali, Member Lok Sabha are appointed as members of the Governing Body for Delhi Milk Scheme as reconstituted vide this Department Resolution of even number dated 14-10-1968.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Delhi Administration, all Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., the President's Sectt., the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General Central Council of Agricultural, Research, the Director General of Health Services, Mayor, Delhi Municipal Corporation, the President, New Delhi Municipal Committee, the Chairman, Delhi Milk Scheme.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of india, for general information.

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhl, the 27th October 1969

No. 22/1/69-CAI(2).—In partial modification of Ministry of Education Notification No. 14/3/65-C5, dated the 23rd April, 1966, Dr. B. C. Chakravorty, Historical Section, Ministry of Defence, is appointed as Ordinary Member of the Indian Historical Records Commission, in place of Dr. S. N. Prasad. The term of his appointment for the present will be up to the 3rd April, 1971.

A. S. TALWAR, Under Secy.

New Delhi, the 31st October 1969

RESOLUTION

Subject: Setting up of Co-ordinating Committe for National Integration Samilis attached to universities and public sector undertakings.

No. F. 5-1/69-NIC.—The National Integration Sub-Committee of the National Committee for Gandhi Centenary had launched a project of setting up National Integration Samitis in various universities and public sector undertakings in connection with the celebrations of Gandhi Centenary for the purpose of promoting mutual understanding and appreciation among persons coming from different parts of India.

As the National Integration Sub-Committee of the National Committee of the Gandhi Centenary is to be wound up, the Government of India has decided to set up a Co-ordinating Committee for National Integration Samitis under the Chairmanship of Education Minister in order to take over the work relating to the National Integration Samitis and to regulate, guide and finance the function of these Samitis under the auspices of the National Integration Council.

Composition:

The Co-ordinating Committee will be composed of:

Chairman

1. Minister of Education and Youth Service Ex-officto

Members

2. Six members drawn from the National Integration Sub-Committee of the National Committee of the Gandhi Centenary and the National Integration Council.

The Ministry of Education & Youth Services will service this Committee and provide the necessary Secretariat.

The tenure of the members of the Committee shall be 3 years from the date of appointment provided that—

- (i) The ex-officio members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee.
- (ii) The nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority, and
- (iii) If a vacancy arises on the Committee due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of 3 years.

Meetings

The Co-ordinating Committee for National Integration Samitis shall meet not less than once a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

Functions

The functions of the Committee shall be:

- To regulate, guide and finance the functioning of the National Integration Samitis under the auspices of the National Integration Council.
- (2) To establish such Samitis in all universities and central public undertakings where they do not exist.
- (3) To broaden and intensify the work of these samitis by encouraging them—
 - to send batches of students with one or two Professors or Lecturers to other linguistic and cultural
 areas so that they may have direct acquaintance of
 the students of that University and people in
 the neighbourhood;
 - (ii) to encourage and assist them to organise seminars on State, Regional or National basis;
 - (iii) to organise lectures, discussions and cultural programmes calculated to promote national integration

and dispel communal, linguistic and other prejudices:

 (iv) to evolve other schemes which will promote national integration in universities and Central Public Undertakings.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi-11, the 23rd October 1969

SUBJECT: -- Constitution of the Board of Rehabilitation.

RESOLUTION

No. 4(8)/69-B.O.R.—The Government of India have accepted the resignation from the membership of the Board of Rehabilitation of Shri A. K. Sen, Managing Director, India Oxygen Limited, Calcutta, whose appointment was notified the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) Resolution No. 3(5)/67-RH.V, dated the 30th January, 1968.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:-

- 1. The Members of the Board.
- The Ministries/Departments of the Government of India.
- The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, and the Private and Military Secretaries to the President.
- 4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. NANJAPPA, Secy.

•		